स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com

दिनांकः– 16.01.2015

–प्रेस विज्ञप्ति–

"शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने फीस निर्धारण की विसंगतियो को दुर करने का आश्वासन दिया"

अजमेर। आज स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ का एक शिष्ट मण्डल शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी से उनके निवास स्थान पर मिला और फीस निर्धारण की विसंगतियो के बारे मे विस्तार से बताया। संघ के अध्यक्ष सत्यव्रत सामवेदी ने शिक्षामंत्री को इस तथ्य से अवगत कराया कि फीस निर्धारण समिति का गठन मुनाफाखोरी रोकने के लिये था परन्तु मुनाफाखोरी रोकने के स्थान पर नाममात्र की फीस लेने वाली शिक्षण संस्थाओ की फीस इतनी कम कर दी की अब उनका संचालन असम्भव हो गया। शिष्ट मण्डल मे शामिल जितेन्द्र अरोड़ा ने बताया की जवाजा ब्लॉक से सनातन धर्म माध्यमिक विधालय की वार्षिक फीस 1650रू से घटाकर मात्र 750रू कर दी। यहा तक कि आदर्श विद्या मन्दिर अतीतमन्द की वार्षिक फीस 3000रू से घटाकर 850रू कर दी। प्रवीण गोयल ने कहा कि हम मुनाफाखोरी के खिलाफ है आप मुनाफाखोरी करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करे हमें कोई आपत्ति नही है। देवनानी ने यह सब सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया ओर कहा कि किसी भी हालत मे संस्थाओ पर अन्याय नही होने देंगे। ओर शीघ्र ही फीस निर्धारण समिति के सदस्य प्रमुख शासन सचिवो ओर अधिकारियो को बुलाकर विसंगतियो को दुर करने के लिये वार्ता करेंगे। ओर इस वार्ता मे गैर सरकारी संस्थाओ के प्रतिनिधि भी होंगे। संघ के महामंत्री एंव मंत्री रतनसिंह पिलानिया एंव किशन मित्तल ने निजी शिक्षण संस्थाओ की समस्याओ के समाधान के लिये 21 सूत्रीय ज्ञापन दिया ओर उन्होने आश्वासन दिया कि इन समस्याओ का शीघ्र ही निराकरण किया जायेगा। देवनानी ने यह भी आश्वासन दिया कि निजी शिक्षण संस्थाओ की समस्याओ के समाधान के लिये शीघ्र ही पंचायत चुनावो के बाद एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमे निजी शिक्षण संस्थाओ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

इससे पूर्व शिष्ट मण्डल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बी.एल. चौधरी से मिला और 2000रू वार्षिक शुल्क लेने का जबरदस्त विरोध किया। पिलानिया और मित्तल ने कहा कि बोर्ड से सम्बन्धित समस्याओ के लिये अजमेर मे प्रान्तीय प्रदर्शन हुआ था। और 25000 संचालको ने बोर्ड के कार्यालय का घेराव किया था। और उसी दिन उन समस्याओ के समाधान के लिये सहमति पत्र जारी हुआ था। इस सहमति के अनुसार राजस्थान सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने सम्बद्वता के लिये मासिक विलम्ब शुल्क मासिक 5000रू निरस्त कर दिया था। और बोर्ड द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित कर दी थी। इस निर्धारित फीस मे वार्षिक शुल्क लिये जाने का कोई उल्लेख नही है। बोर्ड के अध्यक्ष चौधरी ने शिष्ट मण्डल द्वारा प्रस्तुत समस्याओ को ध्यान पूर्वक सुना और कहॉ की आप द्वारा दिये गये ज्ञापन की जांच करा ली जायेगी और कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयो के विरूद्व यदि बोर्ड ने कोई कार्यवाही की है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

शिष्ट मण्डल मे स्वंय सेवी शिक्षण संस्था संघ के अध्यक्ष सत्यव्रत सामवेदी, महामंत्री रतनसिंह पिलानिया, मंत्री किशन मित्तल, संभाग प्रभारी प्रवीण गोयल राजस्थान प्राइवेट एज्यू0 एसो0 राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कैलाशचन्द शर्मा, महासचिव प्रकाशचन्द शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल भाटिया, आल राजस्थान स्कूल एसोसिएशन कोर कमेटी अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष जितेन्द्र अरोड़ा, महामंत्री राजेन्द्र शर्मा थे।

किशन मित्तल
मंत्री
9829523349